



2026:AHC-LKO:39994

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 3927 वर्ष 2026

शिवम गिरी

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : रमाकर शुक्ला

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 12

माननीय न्यायमूर्ति जफ़ीर अहमद

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह आवेदक की ओर से दायर किया गया प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र है, जो अपराध संख्या 117/2026 में धारा 309(4), 309(6), 317(2) भारतीय न्याय संहिता (संबंधित धारा 392, 394 और 411 भारतीय दंड संहिता) के तहत, पुलिस स्टेशन लम्भुआ, जिला सुल्तानपुर में शामिल है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक पर लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं। विद्वान

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिवक्ता ने आगे कहा कि सह-आरोपी सूरज गिरी को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 3770/2026 में दिनांक 26.05.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक की भूमिका सह-आरोपी सूरज गिरी के समान है, जिसे इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि आवेदक उक्त सह-आरोपी के समान न्याय पाने का हकदार है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक 1.4.2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया है। हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान भूमिका निभाने वाले सह-आरोपी को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करने के बाद, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सह-आरोपी, जिसकी भूमिका आवेदक के समान है, को जमानत दी जा चुकी है, आवेदक 1.4.2026 से जेल में बंद है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए इसे उपयुक्त मामला पाता हूं।

7. तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

8. अपराध संख्या 117/2026 में धारा 309(4), 309(6), 317(2) भारतीय न्याय संहिता (संबंधित धारा 392, 394 और 411 भारतीय दंड संहिता) के तहत, पुलिस स्टेशन लम्भुआ, जिला सुल्तानपुर के तहत आरोपी शिवम गिरि को न्याय के हित में निम्नलिखित शर्तों के अधीन

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप इतनी ही राशि के निजी मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/ उसे डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iv) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, अधीनस्थ न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।
- (v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो अधीनस्थ न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।
- (vi) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक संहिता की धारा 209 के तहत विधिवत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और मुकदमे की गुण-दोष पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा।

जून 2, 2026

कन्हैया

(न्यायमूर्ति जफ़ीर अहमद)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।